रोम की एलिस पैस्कीनी एक मल्टी मीडिया आर्टिस्ट हैं जिनके स्ट्रीट आर्ट में इंसानी रिश्तों का खूबसूरत पक्ष नज़र आता है। उनकी कला, स्त्रीत्व, स्वतंत्र महिला जैसे विषयों पर केन्द्रित है। उनके बनाए भित्ति चित्रों, पेंटिंग्स व रेखाचित्रों में प्रेम और करूणा की कहानियां समाहित होती हैं। शहरों की दीवारों पर जगह-जगह उनकी विशाल कलाकृतियां दिखाई देती हैं। वे जिस भी दीवार पर चित्र बनाती हैं पहले उस दीवार के भौतिक गुणों का अध्ययन करती हैं। मटीरियल, दीवार का पेंट, और दीवार पर पड़े विभिन्न निशान व नुकसान (डैमेजेस) उस क्षेत्र के इतिहास और लोगों के बारे में संकेत देते हैं और यही उनकी पेंटिंग का कैनवस होता है। उसके बाद वो स्नेही कपल, बच्चों आदि के चित्र बनाती हैं, जिनके चेहरों पर असाधारण करूणा और सकारात्मकता के भाव होते हैं। एलिस कहती हैं, "मैं इंसानी भावनाओं और उनके रिश्तों को बयान करती हूँ, यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। दुनियाभर की दीवारें एक जरिया हैं एकता का संदेश देने का।" दुनियाभर में दीवारों पर उनके बनाए भित्ति चित्र हैं। उनके अपने शहर रोम के अलावा ऑस्लो और टोरॉन्टो, सिडनी, न्यूयॉर्क, बार्सिलोना, मॉस्को, कोपनहेगन, बर्लिन, व लंदन आदि में उन्होंने भित्ति चित्र बनाए हैं। एलिस इसके लिए खूब यात्राएं करती हैं, शहर की दीवारें उनका प्रिय कैन्वस हैं। रोम की अकैडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की ग्रैजुएट, एलिस ब्रिटेन में रहती हैं और ब्रिटेन के अलावा फ्रांस व स्पेन में भी काम करती हैं।

बिहार में ओवैसी के पांच में से चार विधायकों ने पार्टी छोड़ी

इन विधायकों ने आर.जे.डी. जॉइन की

पटना, 29 जून। बिहार विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पांच में से चार विधायकों के लालू यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल होने के बाद बीजेपी विधानसभा में नंबर 2 पार्टी हो गई है। इससे भाजपा के नेता तिलमिला गए हैं और सुबह से ही लगातार एक साथ तेजस्वी यादव से लेकर ओवैसी तक को कोस रहे हैं।

अब बीजेपी के नेताओं ने आरजेडी में शामिल 4 विधायकों के नंगे पांव राजद सुप्रीमो लालू यादव से मिलने पर तीखा बयान दिया है और कहा है कि अभी तो नाक रगड़ना और जूते घिसना बाकी है।

दरअसल, तेजस्वी यादव दोपहर में ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने की सूचना देने उनको लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास गए।

वहां से निकलकर उन्होंने इन विधायकों के साथ मीडिया से बात की

■ इस घटना पर भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट में लिखा है- "आदरणीय लालूजी स्वस्थ- सुरक्षित रहें हमारी कामना है। उनको छोड़िए। युवराजों के पैर में भी चप्पल है। लेकिन दिलचस्प है किएआईएमआईएम के 4 मुसलमान विधायकों को राजद में लाया गया तो उनको चप्पल उतरवाकर घर में बुलाया गया। अभी तो नाक रगड़ना और जूते घिसना बाकी है।"

उसके बाद तेजस्वी इन विधायकों को पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिलाने लेकर गए थे।

इस मुलाकात की जो फोटो आई उसमें ये चार विधायक नंगे पांव दिख रहे हैं जबकि लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव वगैरह जूता या चप्पल पहने नजर आ रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि लालू के कमरे में जाने से पहले एआईएमआईएम से आरजेडी में आए इन विधायकों ने अपना जूता-चप्पल उतार दिया था।

लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के साथ इन चार विधायकों की फोटो शेयर करते हुए बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने कटाक्ष किया है।

निखिल आनंद ने ट्वीट में लिखा है-"आदरणीय लालूजी स्वस्थ-सुरक्षित रहें हमारी कामना है। उनको छोड़िए। युवराजों के पैर में भी चप्पल है। लेकिन दिलचस्प है किएआईएम आईएम के 4 मुसलमान विधायकों को राजद में लाया गया तो उनको चप्पल उतरवाकर घर में बुलाया गया। अभी तो नाक रगड़ना और जूते घिसना बाकी है।"

मैडिकल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मन्त्रालय चिन्तित है, क्योंकि भारत क्वालिफायड डॉक्टरों की कमी से पहले ही जूझ रहा हैं।

पूरे देश में, कुल मिलाकर 91000 एम.बी.बी.एस. सीटें तथा 42000 पीजी सीटें हैं। पीजी पाठ्यक्रमों में जो सीटें नहीं भरी गई हैं, उनमें 930 सीटें सुपर स्पैशिएलिटी कोर्सों की हैं, जो अब भरी जा रही हैं। स्वास्थ्य मन्त्रालय के सूत्रों ने कहा है कि, प्रबन्धन कोटा की बहुत सी सीटें इसलिये नहीं भरी गई हैं क्योंकि मैडिकल कॉलेज प्रवेश के लिये बहुत अधिक पैसे (प्रीमियम) की माँग करते हैं।

होटल व अस्पताल के रुम व पैकेज्ड अनाज, तेल, मिल्क प्रोडक्ट और महंगे होंगे

जी.एस.टी. काउंसिल की बैठक में इन वस्तुओं पर जी.एस.टी. 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया गया

नई दिल्ली, 29 जून (वार्ता)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा-कर (जीएसटी) परिषद ने बुधवार को दरों को युक्तिसंगत करने और उल्टे शुल्क ढांचे की शिकायतें दूर करने के लिए कई वस्तुओं पर कर में बदलाव किया और कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर छूट वापस लेने का फैसला किया।

इन निर्णयों से बिना ब्रांड के पैकेज्ड अनाज, खाद्य तेल, दुग्ध उत्पाद, होटल और अस्पतालों के कमरे तथा चाकू, पेंसिल शार्पनर और चम्मच-कांटा आदि महंगा हो जाएगा।

सर्वाधिकार सम्पन्न जीएसटी परिषद की आज चंडीगढ़ में सम्पन्न दो दिवसीय बैठक में संशोधित जीएसटी की दरें अब 18 जुलाई से लागू हो जाएंगी।

■ इसके अतिरिक्त चाकू, पैंसिल शॉर्पनर, चम्मच-कांटा, इसी तरह बीजों, अनाज और दालों की सफाई, छँटाई या ग्रेडिंग की मशीनों, अनाज मिलों में प्रयुक्त मशीनरी, पवन चक्की और वेट ग्राइंडर पर कर की दर पांच प्रतिशत की जगह 18 लागू होगी।

बैठक की जानकारी देते हुए परिषद की अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने कई वस्तुओं पर जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) को संशोधित करने की सिफारिश की है।

बैठक के बाद जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार नये निर्णयों से चाकू, कागज के चाकू, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स और केक-सर्वर पर जीएसटी की दर 12 से बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगी।

इसी तरह बीजों, अनाज और दालों की सफाई, छँटाई या ग्रेडिंग की मशीनों, अनाज मिलों में प्रयुक्त मशीनरी, पवन चक्की और वेट ग्राइंडर पर कर की दर पांच प्रतिशत की जगह 18 लागू होगी।

इस निर्णय से होटल के अपेक्षाकृत सस्ते कमरों पर जीएसटी लागू होने से ये कमरे महंगे होंगे। अब 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम के किराए वाले होटल कक्ष के लिए 12 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। इसी तरह प्रति मरीज 5,000 रुपये प्रतिदिन से अधिक के अस्पताल के कमरे का किराया (आईसीयू को छोड़कर) पांच प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आएगा और इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा।

जीएसटी परिषद ने बैंक चेक पर कर छूट को वापस लेने और 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का भी फैसला किया। मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्ट, जिनमें एटलस, वॉल मैप, स्थलाकृतिक योजना वाले मानचित्र और ग्लोब पर जीएसटी की छूट खत्म की जा रही है और इन पर 12 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा।

विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर पांच प्रतिशत की रियायती जीएसटी दर से जीएसटी लगेगी, भले ही बैटरी पैक से सुसज्जित हैं या नहीं। विज्ञप्ति के अनुसार, कंपोजीशन करदाताओं को कुछ शर्तों के अधीन ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से राज्य के भीतर आपूर्ति करने की अनुमति होगी।

कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि दरों में बढ़ोतरी से कुछ हद तक मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ेगा लेकिन यह कदम सही दिशा में था। पीडब्ल्यूसी इंडिया के पार्टनर प्रतीक जैन ने कहा, अलग-अलग मदों पर दरों में बढ़ोतरी पर हमेशा दो नजरिए होंगे लेकिन जीएसटी परिषद का फैसला सही है क्योंकि यह उल्टे कर ढांचे की शिकायत दूर करता है और इसमें छूट करने का प्रयास करता है।

मुकेश अंबानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत हुये सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सूर्यकान्त तथा जमशेद बी पर्दीवाला की बैंच को बताया कि, मुम्बई में अम्बानी परिवार को दी गई सुरक्षा का विषय त्रिपुरा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता ही नहीं हैं।

अब इस प्रकरण की सुनवाई अगले महीने होने की सम्भावना है।

मेहता ने सोमवार को बैंच से कहा था कि, त्रिपुरा उच्च न्यायालय की जानकारी में यह लाया जा चुका है कि, बम्बई उच्च न्यायालय इसी प्रकार की एक याचिका को खारिज कर चुका है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय का इस पी.आई.एल. से कोई लेना देना ही नहीं था क्योंकि यह उसके क्षेत्राधिकार से बाहर की चीज थी।

केन्द्र ने कहा कि, उच्च न्यायालय ने यह आदेश एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की गई पी.आई.एल. पर दिया, जिसकी इस मामले में कोई अधिकारिता (लोकस स्टैन्डाई) ही नहीं थी। वह मात्र अनावश्यक दखलंदाजी करने वाला व्यक्ति था, जो स्वयं को विद्यार्थी एवं सोशल ऐक्टिविस्ट बता रहा था।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "सादर निवेदन है कि, पूरी तरह से भ्रान्त, सारहीन तथा अभिप्रेरित (मोटिवेटेड) पी.आई.एल. याचिका, जिसमें किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन की बात तक नहीं कही गई है, में माननीय उच्च न्यायालय ने एक ऐसे निर्णय की न्यायिक समीक्षा के क्षेत्राधिकार में काम किया है, जो निर्णय सार्वजनिक व्यवस्था तथा व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित, विशेषज्ञों द्वारा लिया गया था।"

केन्द्र ने दलील दी कि उच्च न्यायालय की जानकारी में यह बात भी लाई गई थी कि, सुरक्षाबलों द्वारा प्राप्त की गई खतरे एवं आंशका की रिपोर्ट के आधार पर, मुकेश अम्बानी को 2013 में "ज़ैड प्लस" सुरक्षा प्रदान की गई थी तथा प्रतिवादी नीता अम्बानी को 2016 में "वाय प्लस श्रेणी" का सुरक्षा कवर दिया गया था। केन्द्र ने आगे कहा, "उच्च न्यायालय को यह भी बता दिया गया था कि, प्रतिवादी नं. 2 तथा 3 को ये दोनों सुरक्षा कवर, गुप्तचर तथा जाँच-पड़ताल इकाइयों से प्राप्त सूचनाओं एवं आकलन रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था तथा इस प्रकार का सुरक्षा कवर दिये जाने का पूरा खर्चा दोनों ही संदर्भित प्रतिवादी विधिवत वहन कर रहे थे।

उदयपुर घटना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साथ ही खुफिया एजेंसियों में खलबली मच गई थी, क्योंकि जिस तरीके से कन्हैयालाल को मारा गया, वह तालिबान या आईएसआईएस का तरीका था। इस घटना के बाद आरोपियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर अपने मंसूबे साफ कर दिए थे, जिस तरह से तालिबानी दहशत फैलाते हैं।

इस घटना के बाद उदयपुर आई एनआईए टीम की जांच में गौस और रियाज के पाकिस्तानी कनैक्शन के पुख्ता सबूत मिले हैं। बताया जाता है कि इन दोनों ने कराची से लौटने के बाद उदयपुर में युवाओं को भड़काना शुरू कर दिया था। घटना को लेकर टीम ने उदयपुर में कन्हैयालाल की दुकान पर काम करने वाले कारीगर राजकुमार से भी पूछताछ की है। अब तक की जांच के अनुसार रियाज पाकिस्तान में कराची के एक मौलाना के संपर्क में था और जिस तरह से कन्हैयालाल का मर्डर किया गया है, वह पूरी तरह से सोची समझी साजिश का हिस्सा था। दोनों मिलकर इस तरीके से समाज मे दहशत फैलाना चाहते थे। इसी के चलते कराची से लौटने के बाद रियाज और गौस मौहम्मद ने वॉट्सऐप ग्रुप बनाए थे। इस ग्रुप के जरिए ही रियाज भड़काऊ वीडियो भेजकर युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे।

पाकिस्तान को आशा की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है, कीमतें बढ़ रही हैं और प्रतिदिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन सब की बेहद कमी है।

पाकिस्तान अब अपनी आधारभूत जरूरतों को सऊदी अरब के उदार दान से थोड़ा बहुत पूरा कर सकता है और उसके द्वारा दिए गए एक बड़े ऋण का धन पहले ही खर्च हो चुका है, इसलिए सऊदी अरब से अगला ऋण मिलना भी असंभव लगता है।

अब ऐसा लगता है कि, कुछ मदद मिल सकती है। देश ने 6 मिलियन डॉलर के अवरूद्ध कर दिए गए अपने "बेल आउट पैकेज" में से कम से कम 1 बिलियन डॉलर का फण्ड तुरन्त प्रभाव से जारी करने के लिए इन्टरनैशनल मॉनिटरी फण्ड (आई.एम.एफ.) से बातचीत शुरु कर दी है। तथापि आई.एम.एफ. ने किसी तरह का फण्ड देने से पूर्व कठोर शर्तें लगाई हैं।

■ पर, मूल बात है, चीन द्वारा पाकिस्तान में लगवाए इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजैक्टस के लिये चीन से मिले उधार की अदायगी। जैसे कि, गवादार बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट, जिनका कोई इकोनॉमिक रिटर्न फिलहाल मिलने की कोई संभावना नहीं।

फण्ड जारी करने की आई.एम.एफ. की सबसे महत्वपूर्ण पहली पूर्व शर्त है कि, देश में मौजूद व्यापक भ्रष्टाचार पर निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाए क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण सार्वजनिक धन निजी लोगों के जेबों में जा रहा है।

पाकिस्तान के हाल ही सत्ताच्युत किए गए प्रधानमंत्री इमरान खान ने बार-बार कहा था कि, परम्परागत राजनीतिक दलों के शासन में हुए निरंकुश भ्रष्टाचार ने ही पाकिस्तान को आर्थिक दलदल में धकेला।

संयोगवश, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री के भाई नवाज़ शरीफ़ पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते रहे हैं तथा उन्हें देश के किसी भी निर्वाचित पद पर चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा चुका है।

विश्वास मत में इमरान खान की सत्ता से बेदखली के बाद नए प्रधानमंत्री बने, शाहबाज शरीफ़ ने कुछ जरूरी चीज़ों का आयात करने और अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आई.एम.एफ. के साथ ताजा बातचीत शुरु की है।

आई.एम.एफ. की अन्य शर्तों में पैट्रोलियम उत्पादों पर कम से कम 50 रूपए प्रति लीटर टैक्स लगाकर इसकी खुदरा कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी करना, 43,600 करोड़ पाकिस्तानी रूपयों का अतिरिक्त कर संग्रहण और बिजली के बिलों में वृद्धि करना शामिल है।

गिरती अर्थव्यवस्था और विश्वसनीयता में तेजी से आई कमी के कारण पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से फण्ड्स नहीं जुटा पा रहा है। इसके अतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के निर्माण में चीन के बड़े निवेश के कारण पाकिस्तान पर चीन का भारी कर्ज है। इन फैसिलिटीज़ के प्रोजैक्ट इतने बड़े हैं कि देश इनका आर्थिक उपयोग करने के लिए समर्थ नहीं है।

इन प्रोजैक्ट्स में से, अरब सागर तट पर बनने वाला गवादार पोर्ट प्रोजैक्ट है। चीन अरब सागर में अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसे एक मिलिटरी बेस के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है। ये प्रोजैक्ट्स वाणिज्यिक स्तर पर कोई लाभ नहीं दे रहे हैं।

चूंकि इन मंहगी फैसिलिटीज़ का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए इनकी वित्तीय लागत ही पाकिस्तान के ऋणों का भार बढ़ा सकती है।

इनमें से एक भी प्रोजैक्ट ऐसे देश में लोकप्रिय नहीं हो सकता, जिसकी महंगाई दर दोहरे अंकों में है और जहां आर्थिक व्यवधान हैं।

गुरूवार को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सकेंगे। इस दौरान रैली, सभा, जुलूस-प्रदर्शन पर रोक रहेगी। इसकी पूर्व अनुमति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से लेनी जरूरी होगी। जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। सिर्फ सिख समाज के लोगों को कृपाण धारण करने की छूट होगी।

63 हजार ग्रामीण सहकारिता इकाइयों का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा

सरकार का अनुमान है कि, इससे सीधे तौर पर 13 करोड़ किसान लाभान्वित हो सकेंगे

नई दिल्ली, 29 जून (वार्ता)। देश में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास और सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए 63 हजार प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा तथा इसके लिए प्रत्येक समिति पर लगभग चार लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। कुल 2516 करोड़ रुपये की लागत से पैक्स का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा जिससे 13 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इन किसानों में ज्यादातर छोटे और सीमांत हैं। इससे पैक्स को पंचायत स्तर पर नॉडल डिलीवरी सेवा केन्द्र के रूप में तैयार करने में मदद मिलेगी।

डाटा स्टोरेज के साथ क्लाउड आधारित एकीकृत साफ्टवेयर,साइबर सुरक्षा, हार्डवेयर, मौजूदा अभिलेखों का डिजिटलीकरण,अनुरक्षण और प्रशिक्षण इसके मुख्य घटक हैं।

सहकारिता मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पंचायत स्तर पर सहकारिता की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए देशभर में अगले पांच वर्ष में तीन लाख प्राथमिक कृषि साख समितियों का गठन किया जायेगा। एक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण पर कुल 3.91 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे, इनमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 75 प्रतिशत होगा जबकि शेष राशि राज्य और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) उपलब्ध करायेंगे।

पैक्स के कार्य क्षेत्र में व्यापक विस्तार किया गया है और इसके लिए बैंक मित्र भी काम करेंगे।

राजसमंद में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जानकारी के अनुसार भीम थाने पर ड्यूटी दे रहे कॉन्स्टेबल संदीप चौधरी का किसी धारदार हथियार से गला कटने की सूचना पर जिल जिला पुलिस प्रशासन अल र्ट हो गया और घायल कांस्टेबल को ब्यावर के राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने के चल ते ब्यावर से ग्रीन कोरिडोर बनाकर उसे अजमेर के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल ल ाया गया। जहां पहले से मुस्तैद चिकित्सकों की टीम ने आईसीयू में ले जाकर उसका उपचार शुरू कर दिया। जिला कलैक्टर अंशदीप और पुलि स अधीक्षक विकास शर्मा भी अपने लवाजमें के साथ अस्पताल में मौजूद रहे।

इस दौरान जेएल एन अस्पताल पूरी तरह से पुलि स छावनी बना रहा।

जिला कलैक्टर अंशदीप ने बताया कि अजमेर में किसी तरह की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े इसके लिए धारा 144 लागू की गई है।

6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होंगे

■ चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी की।

नई दिल्ली, 29 जून (वार्ता)। देश के 16वें उपराष्ट्रपति का चुनाव छह अगस्त को होगा। चुनाव आयोग ने आज यहां उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। कार्यक्रम के अनुसार पांच जुलाई को उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी और उसके बाद से नामांकन प्रारंभ हो जाएगा और नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई होगी। उम्मीदवार स्वयं अथवा उनके प्रस्तावक एवं अनुमोदक किसी भी कार्य दिवस में 11 बजे से तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 22 जुलाई तक नाम वापस लिये जा सकेंगे।

यदि आवश्यक हुआ तो शनिवार छह अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक मतदान कराया जाएगा और उसी दिन मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना होगी।

मतदान संसद भवन परिसर में होगा। मतदान स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित 233 एवं मनोनीत 12 सदस्य तथा लोकसभा के निर्वाचित 543 सदस्य मतदान में भाग लेंगे। इस प्रकार से कुल 788 सांसदों का निर्वाचक मंडल होगा।

उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने का विकल्प अपनाया, फ्लोर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने कहा, "मैं अप्रत्याशित रूप से सत्ता में आया था तथा मैं उसी तरह से बाहर जा रहा हूँ।

राज्यपाल के आदेश का पूर्वाभास होने के कारण, पूर्व एम.वी.ए. मन्त्री एकनाथ शिन्दे के नेतृत्व वाले शिवसेना के विद्रोही विधायकों को असम से मुम्बई लाने की व्यवस्था हो चुकी थी। ज्ञातव्य है कि, इन विद्रोही विधायकों ने मुम्बई लौटने की ठाकरे की अपील की अनसुनी कर दी थी। इस बीच ये लोग वोटिंग के लिये गुवाहाटी से आज गोवा आ गये हैं।

एम.वी.ए. गठबंधन सरकार, जो शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) तथा कांग्रेस जैसी विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों को एक साथ इसलिए लाई, ताकि भाजपा को अपने पूर्व पार्टनर शिवसेना को अपने नियन्त्रण में रखने से रोका जाये। लेकिन एम.वी.ए. सरकार इस परस्पर सहयोग को लम्बे समय तक नहीं चला पाई।

ऑप्रेशन "एम.वी.ए. सरकार को अपदस्थ करो" 22 जून को शुरू हुआ था, जिसकी पटकथा निरन्तर अपडेट की जा रही थी। यह ऑपरेशन किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था, जिसमें खुद को बचाये रखने की कोशिशें भी दिखाई दीं, तो करोड़ों रूपयों का खर्च भी दिखाई दिया, जो सूरत से गुवाहाटी तथा अब गुवाहाटी से गोवा तक की चार्टर्ड उड़ानों तथा इतने दिनों तक 60 लोगों के पंच सितारा होटल में ठहरने पर हुआ होगा।

इस बीच, शक्ति परीक्षण से पहले लिये गये अंतिम निर्णयों में से एक निर्णय के अंतर्गत, शिव सेना के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर "सम्भाजीनगर" करने तथा उस्मानाबाद का नाम बदलकर "धाराशिव" कर देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। नाम बदले जाने की प्रक्रिया को शिव सेना के हिन्दुत्ववादी एजेन्डा को चमकाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इन दो नगरों के नाम बदलने का निर्णय शिव सेना ने ऐसे समय पर लिया है, जब वह एक गंभीर राजनैतिक संकट का सामना कर रही है तथा पार्टी विधायकों के एक बड़े समूह ने पार्टी छोड़ दी है।

टीम ठाकरे ने सर्वोच्च न्यायालय पहुंचकर यह दलील दी थी कि, राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी का आदेश गैर कानूनी है क्योंकि 16 विद्रोही विधायकों ने अभी तक अपनी संभावित डिसक्वालिफिकेश के नोटिसों का जवाब नहीं दिया है। राज्यपाल द्वारा शक्ति-परीक्षण का आदेश दिये जाने से एक दिन पहले, भाजपा नेताओं ने उनसे भेंट की थी तथा उनसे कहा था कि, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार अपना बहुमत खो चुकी है।

मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में, कोशियारी ने कहा था कि, उन्हें भाजपा तथा अन्य विधायकों के पत्र मिले हैं, जिनमें कहा गया है कि सरकार अब अल्पमत में आ गई है। राज्यपाल ने लिखा था, "यह स्पष्ट है कि शिव सेना के अधिकांश विधायकों ने स्पष्ट संकेत दे दिये हैं कि वे महा विकास अघाड़ी सरकार से निकलना चाहते हैं। तथा आप अपने विधायकों तथा कार्यकर्ताओं के मन को जीतने के लिये ऐसी कोशिशें कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक नहीं है।"

पत्र में आगे लिखा था, "इसलिये मुझे विश्वास है कि आप और आपकी सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है तथा सरकार अल्पमत में आ गई है।"

गवर्नर ने कहा था कि, शक्ति परीक्षण का लाइव टेलीकास्ट होगा तथा विधानसभा सचिवालय द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से सदन की सारी कार्यवाही कैमरे में रिकॉर्ड की जायेगी। कोशियारी ने यह भी कहा, "स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, इसे सम्पन्न करने के लिये, सदस्यों से कहा जायेगा कि वे वोटों की गिनती के लिये अपनी सीटों पर खड़े हो जायें।"

राज्यपाल द्वारा शक्ति-परीक्षण के आदेश दिये जाने से एक दिन पहले, देवेन्द्र फड़नविस के नेतृत्व में भाजपा नेता उनसे मिले थे तथा उनसे कहा था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला गठबन्धन बहुमत खो चुका है।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि, राज्यपाल ने "जैट की गति से" काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा में मतदान कराने का आदेश गैरकानूनी है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक विद्रोही विधायकों के डिसक्वालिफिकेशन के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया है। शिवसेना का तर्क था ,जिन 16 विधायकों को डिसक्वालिफिकेशन नोटिस दिये गये हैं, वे उस समय तक पटल-परीक्षण में भाग नहीं ले सकते, जब तक अदालत उनकी स्थिति के बारे में निर्णय नहीं दे दे।

करीब 40 शिवसेना विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिन्दे के साथ चले गये हैं, जो पहले तो मुम्बई से सूरत गये थे तथा उसके बाद, सूरत से असम के गुवाहाटी शहर में चले गये थे। उनके साथ विधायकों का वह गुट भी था, जो दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा था। गुवाहाटी के एक पंचसितारा होटल में एक सप्ताह तक ठहरने के बाद विद्रोही विधायक विमान से गोवा आ गये, ताकि वे अविश्वास प्रस्ताव के मतदान में भाग ले सकें। ज्ञातव्य है कि गोवा मुम्बई से 600 किमी की दूरी पर है।

शिन्दे ने आज गुवाहाटी में पत्रकारों को बताया, "हम कल मुम्बई पहुँच जायेंगे। हमारे साथ 50 विधायक हैं हमारे पास दो-तिहाई बहुमत है। हम पटल-परीक्षण को लेकर बिल्कुल भी चिन्तित नहीं हैं। हम इस परीक्षण में सफल होंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। लोकतन्त्र में बहुमत भी अर्थ रखता है तथा हमारे पास बहुमत है।"

शिन्दे तथा कुछ विद्रोही विधायक आज सुबह ब्रहमपुत्र नदी में होकर असम के मुख्य शहर में स्थित कामाख्या मन्दिर गये थे, जहाँ उन्होंने पत्रकारों को बताया है कि वे कल मुम्बई लौट जायेंगे।

इससे पूर्व, ठाकरे ने डिप्टी स्पीकर से कह दिया था कि वे 16 विधायकों, जिनमें शिन्दे भी शामिल थे, को डिसक्वालिफाई कर दें। इसके बाद विद्रोही गुट सर्वोच्च न्यायालय पहुँच गया था तथा उसने अपने खिलाफ हुई कार्यवाही को गैर कानूनी बताया था। अदालत ने विद्रोही विधायकों को अपनी सम्भावित डिसक्वालिफिकेशन का जवाब देने के लिये 12 जुलाई तक का समय दे दिया था।

शिन्दे का दावा है कि उन्हें करीब 50 विधायकों का समर्थन हासिल है, जिनमें से करीब 40 विधायक शिवसेना से हैं। 287 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आँकड़ा 144 है। शिवसेना, कांग्रेस तथा एन.सी.पी. के सत्तारूढ़ गठबन्धन के पास 152 विधायक हैं। 40 विद्रोही विधायकों के बिना, राज्य सरकार अल्पमत में आ जायेगी।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908